

इस मानसून में 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा भजनलाल सरकार ने

प्रदेश में नमो वन एवं नमो नर्सरी तथा चंदन वन की स्थापना की जाएगी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश को हरित बनाने के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि "हरियालो राजस्थान" राज्य सरकार की प्राथमिकता है। आगामी मानसून सीजन में 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय में वन एवं पर्यावरण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने और पौधारोपण कार्य को निरंतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी विभागों को सक्रिय भागीदारी आवश्यक है और मुख्य सचिव स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा की जाए।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने "हरियालो राजस्थान" को लेकर शनिवार को वन एवं पर्यावरण विभाग की समीक्षा बैठक की। इस मौके पर वन राज्यमंत्री संजय शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, आनंद कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पौधारोपण अभियान को शुरूआत विश्व पर्यावरण दिवस से होगी, जबकि जुलाई, अगस्त और सितंबर में इसे व्यापक स्तर पर गति दी जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग पहले से स्थान चयन, गड्डे तैयार करने और फेंसिंग जैसे कार्य समय पर पूरे कर लें। शर्मा ने कहा कि राजस्व विभाग के सहयोग से उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाए। साथ ही भारतीय

रेलवे के साथ समन्वय कर रेलवे परिसरों पर भी पौधारोपण किया जाएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रमुख सड़कों और चारागाह भूमि पर वृक्षारोपण की योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने मिट्टी की उत्पादकता के अनुरूप पौधारोपण करने और विशेष रूप से गूलर जैसे वृक्षों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।

उन्होंने सीएसआर के माध्यम से पौधों की सिंचाई के लिए टैकर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा "वृक्षमंत्रों" की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। 'मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान' के तहत किसानों को नि:शुल्क फलदार पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही उदयपुर, सिरोंही और बांसवाड़ा जिलों में चंदन वन विकसित करने की योजना पर भी काम किया जाएगा, जिसमें ड्रिप सिंचाई और तारबंदी जैसी व्यवस्थाएं की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में 'नमो नर्सरी' स्थापित करने और पंचायत समिति स्तर पर 'नमो वन' विकसित करने की योजना को प्राथमिकता से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने पहाड़ी और वन क्षेत्रों में

■ पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों में ड्रोन सिडिंग की जाएगी, किसानों को फलदार पौधे दिए जाएंगे

■ रेलवे परिसरों, प्रमुख सड़कों के पास तथा चारागाह भूमि में वृक्षारोपण करें : मुख्यमंत्री

ड्रोन सिडिंग तकनीक के उपयोग को भी बढ़ावा देने की बात कही।

उल्लेखनीय है कि 'मिशन हरियालो राजस्थान' के तहत वर्ष 2024 से 2028 तक कुल 50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2024 में 7.22 करोड़ और 2025 में 11.74 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं, जो निर्धारित लक्ष्यों से अधिक है। बैठक में वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री संजय शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, आनंद कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े।

खनन क्षेत्र के ऑटोमाइज्ड अधिकृत तुलाई कांटों का 8 जुलाई को लाइव परीक्षण

व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम से जुड़ेंगे खनिज परिवहन वाहन : एसीएस माइंस

■ फील्ड अधिकारी बनाए सहायक नोडल अधिकारी, मांडपूल इंस्टालेशन व लाइव कराने का अहम दायित्व : अपर्णा अरोरा

जयपुर । राज्य में खनन क्षेत्र के ऑटोमाइज्ड अधिकृत तुलाई कांटों का 8 अप्रैल से लाइव परीक्षण आरंभ किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम अपर्णा अरोरा ने बताया कि माइनिंग सेक्टर में राज्य के खानधारकों और राज्य सरकार दोनों के व्यापक हितों को देखते हुए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम आरएफआईडी चालू करने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने बताया कि पहले चरण में वे-त्रिज ऑटोमाइजेशन और जीपीएस आरएफआईडी आधारित व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम वीडियो से मांडपूल तैयार कर चरणबद्ध तरीके से तुलाई कांटों और खनिज परिवहन वाहनों के ऑटोमाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। विभाग के संबंधित फील्ड अधिकारियों को अवकाश के दिनों में भी ऑटोमाइजेशन का कार्य जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

एसीएस माइंस एवं पेट्रोलियम अपर्णा अरोरा ने बताया कि राज्य सरकार के उन्नत कार्यक्रम में आरएफआईडी के कार्य को शामिल किया गया है और यह कार्य अनवरत होने के बावजूद अगस्त तक तुलाई

सेक्टर में पारदर्शिता और व्यवस्था का सरलीकरण हो सकेगा। इससे सबसे अधिक लाभ खानधारकों को होगा वहीं राज्य सरकार के राजस्व में होने वाली छीजत पर भी रोक लग सकेगी।

अधीक्षक खनि अभियंता जयपुर एनएस शकतावन ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती अरोरा जयपुर एएसएमई कार्यक्रम के चयनित तुलाई कांटों के ऑटोमाइजेशन के कार्य को लाइव करेगी। इसके साथ ही ऑटोमाइज्ड कांटों का लाइव प्रदर्शन शुरू हो जाएगा।

अतिरिक्त निदेशक मुख्यालय एवं नोडल अधिकारी आरएफआईडी महेश माथुर ने बताया कि विभाग के खनि अभियंताओं और सहायक खनि अभियंताओं को सहायक नोडल अधिकारी बनाते हुए उन्हें चिन्हित तुलाई कांटों और खनिज परिवहन वाहनों में ऑटोमाइजेशन के कार्य को तय समय सीमा में कराने के निर्देश दिए गए हैं। हाईब्रिड बैठक में निदेशक माइंस महावीर प्रसाद मीणा, संयुक्त सचिव अरविन्द सारस्वत, विशेषाधिकारी श्रीकृष्ण शर्मा, अतिरिक्त निदेशक आईटी शौतल अग्रवाल व संबंधित अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

देवदूत बने राजस्थान पुलिस के जांबाज

जयपुर । ब्रह्मपुरी इलाके में शुकुवार शाम का मंजर किसी डरावने सपने से कम नहीं था। तेज अंधड़ और बारिश ने एक टीन शेड वाले घर को पलभर में मलबे में बदल दिया था। मलबे के नीचे दबी कराहती व मदद को पुकारती एक महिला... ऊपर लिखते टोन के टुकड़े... और चारों तरफ फैले टूटे बिजली के तार, जिनमें दौड़ रहा था करंट। हर सेकंड खतरा बढ़त हा था, हर पल मौत करीब आ रही थी।



ब्रह्मपुरी इलाके में मलबे में दबी परिवार को पुलिसकर्मियों को सुरक्षित बाहर निकालकर जान बचाई।

बिजली के खुले तारों को देखकर कोई भी शख्स महिला को निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था लेकिन तभी मिली सूचना पर बिजली की गति से वहां पहुंचे दो चेहरे-हेड कांस्टेबल भागीरथ और चालक हंसराज-जो उस दिन सिर्फ पुलिसकर्मी नहीं, बल्कि जिंदगी की आखिरी उम्मीद और देवदूत बनकर आए। हालात ऐसे थे जहां एक कदम आगे बढ़ाना भी जान जोखिम में डालने जैसा था। मगर इन दोनों ने न हालात देखे, न खतरा... बस देखा तो एक जिंदगी, जो मदद को पुकार रही थी। करंट से भरे तारों के बीच, मलबे को हटते हुए, हर पल खतरे से जुझते हुए उन्होंने उस महिला तक पहुंच बनाई। पसीने, डर और जोखिम के बीच आखिरकार उन्होंने उसे बाहर खींच लिया-जैसे मौत के मुंह से

जिंदगी छीन ली हो। इसके बाद बिना समय गंवाए महिला को तुरंत एएसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां अब वह सुरक्षित है। यह सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं था... यह उस जवने की कहानी थी, जहां वरदी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इंसायनित का प्रतीक बन जाती है। जब हर कोई पीछे हट जाता है, तब यही पुलिसकर्मी आगे बढ़ते हैं... और साबित कर देते हैं-आइए वक्त में पुलिस सिर्फ कानून नहीं, जिंदगी भी बचाती है।

"ग्राम-2026" के लिए देशभर में आयोजित होंगे रोड-शो

■ जयपुर सहित नई दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे में निदेशकों और एग्रीटेक कंपनियों से होगा संवाद

राजस्थान को कृषि निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करना तथा कृषि क्षेत्र में नवाचार, आधुनिक तकनीकों और आईटी आधारित समाधानों को बढ़ावा देना है। इन आयोजनों के दौरान संभावित निवेशकों, एग्रीटेक डेवलपर्स, उद्योग प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं के साथ संवाद स्थापित करते हुए राज्य में कृषि आधारित उद्योगों, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन से जुड़े अवसरों पर चर्चा की जाएगी। रोड शो के दौरान प्रतिभागियों को तकनीकी सत्र, कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां, स्मार्ट फार्म एवं पशु प्रदर्शनी, बिजनेस-टू-बिजनेस और बिजनेस-टू-गवर्नमेंट बैठकें तथा निवेश संवाद के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। रोडशो का उद्देश्य

जयपुर । राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा 23 से 25 मई को आयोजित होने जा रहे ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम)-2026 के प्रचार-प्रसार और निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से देशभर के प्रमुख शहरों में रोडशो आयोजित किए जाएंगे। ये रोड-शो 10 अप्रैल को जयपुर, 17 अप्रैल को दिल्ली, 24 अप्रैल को अहमदाबाद, 6 मई को हैदराबाद तथा 8 मई को पुणे में होंगे। प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यमिता मंजू पंचोली ने बताया कि ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 मई माह में की जाएगी। इन रोड-शो के माध्यम से निवेशकों,

जयपुर सहित नई दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे में निदेशकों और एग्रीटेक कंपनियों से होगा संवाद

एनर्जी मिक्स से करें ऊर्जा की दीर्घकालिक मांग का समुचित प्रबंधन : केन्द्रीय विद्युत सचिव

पीक ऑवर्स में बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर । केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल ने दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के मिश्रण (एनजी



केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल ने शनिवार को विद्युत भवन में राज्य के एनर्जी सेक्टर से संबंधित विषयों पर चर्चा की।

■ पीएम कुसुम में अब तक करीब 3800 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं राजस्थान में स्थापित हो चुकी : आरती डोगरा

सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा मिला है। केन्द्रीय विद्युत सचिव ने कहा कि डिसेंट्रलाइज्ड सोलर परियोजनाएं विकसित होने के बाद ग्रिड में उत्पादित सौर ऊर्जा के इंटीग्रेशन की चुनौती भी पैदा हो रही है। ऐसे में वितरण निगम ग्रिड स्थिरता को दिशा में स्वयं को बेहतर तरीके से तैयार करें। उन्होंने पीक ऑवर्स में बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित अन्य परियोजनाओं को समय पर विकसित करने पर जोर दिया।

केन्द्रीय विद्युत सचिव ने राज्य के 24 जिलों में कृषि क्षेत्र को दिन में सफाई, लॉस रिडक्शन, आरडीएसएस योजना के अन्तर्गत स्मार्ट मीटर की प्रगति, रिसोर्स एडोप्टिवेसी प्लान आदि पर चर्चा की। उन्होंने प्रदेश में ट्रांसमिशन परियोजनाओं के विस्तार, एस्टीमेटेड नेटवर्क पर नवीकरणीय ऊर्जा को कनेक्टिविटी आदि की भी जानकारी ली। इस अवसर पर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) के सीएमडी जितेंद्र श्रीवास्तव भी उपस्थित थे। ऊर्जा विभाग की शासन सचिव आरती डोगरा ने केन्द्रीय विद्युत सचिव को अवगत कराया कि पीएम कुसुम में अब तक करीब 3800 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित हो चुकी

हैं। उन्होंने जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा लॉस रिडक्शन की दिशा में किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी दी। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रोहित गुप्ता, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ सिहाग, उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक देवेन्द्र श्रुंगी ने भी केन्द्रीय सचिव को संबंधित विषयों से अवगत कराया। इस दौरान केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय के संयुक्त सचिव (वितरण) शशोक मिश्रा सहित केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

हाईकोर्ट ने खारिज की पीआईएल

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सांगानेर न्यायालय में पारिवारिक मामलों का क्षेत्राधिकार दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा व जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह निर्देश पारिवारिक न्यायालय बार एसोसिएशन जयपुर के तत्कालीन महासचिव विष्णु शर्मा की जनहित याचिका पर दिया। याचिका में कहा कि आमजन को सुलभ न्याय देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 24 अगस्त 2022 के आदेश से सांगानेर नर्सरी एवं चौमू के एडोजे न्यायालय को पारिवारिक न्यायालय का क्षेत्राधिकार दिया था। इसके पालन में ही हाईकोर्ट ने 30 अगस्त को आदेश पारित किया। जिसे जनहित याचिका में चुनौती दी गई। एसोसिएशन में सांगानेर नर्सरी एवं चौमू के तत्कालीन अध्यक्ष महावीर सुरेंद्र जैन व महासचिव नेमीचंद सामरिया ने पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र दायर किया। सांगानेर बार एसोसिएशन की ओर से पैरवी करते हुए सीनियर एडवोकेट सुरेश पारीक व अधिवक्ता मनु पंचोली ने बताया कि मामलों का क्षेत्राधिकार पूर्व से एडोजे कोर्ट को दिया जा चुका है। प्रदेश में भी सभी मुख्यालयों पर एडोजे कोर्ट को ही पारिवारिक मामलों का क्षेत्राधिकार है। ऐसे में जनहित याचिका को खारिज किया जाए।

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सांगानेर न्यायालय में पारिवारिक मामलों का क्षेत्राधिकार दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा व जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह निर्देश पारिवारिक न्यायालय बार एसोसिएशन जयपुर के तत्कालीन महासचिव विष्णु शर्मा की जनहित याचिका पर दिया। याचिका में कहा कि आमजन को सुलभ न्याय देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 24 अगस्त 2022 के आदेश से सांगानेर नर्सरी एवं चौमू के एडोजे न्यायालय को पारिवारिक न्यायालय का क्षेत्राधिकार दिया था। इसके पालन में ही हाईकोर्ट ने 30 अगस्त को आदेश पारित किया। जिसे जनहित याचिका में चुनौती दी गई। एसोसिएशन में सांगानेर नर्सरी एवं चौमू के तत्कालीन अध्यक्ष महावीर सुरेंद्र जैन व महासचिव नेमीचंद सामरिया ने पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र दायर किया। सांगानेर बार एसोसिएशन की ओर से पैरवी करते हुए सीनियर एडवोकेट सुरेश पारीक व अधिवक्ता मनु पंचोली ने बताया कि मामलों का क्षेत्राधिकार पूर्व से एडोजे कोर्ट को दिया जा चुका है। प्रदेश में भी सभी मुख्यालयों पर एडोजे कोर्ट को ही पारिवारिक मामलों का क्षेत्राधिकार है। ऐसे में जनहित याचिका को खारिज किया जाए।

चाकसू में पति ने पत्नी की चाकू से गला रेतकर हत्या की

जयपुर । चाकसू क्षेत्र के स्वामी का बास गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पति ने पत्नी को चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी और पूरी रात शव के पास बैठा रहा। घटना शुकुवार देर रात की बताई जा रही है। थानाधिकारी मनोहर लाल के अनुसार सांगानेर के रथपुर निवासी सुनीता (25) की शादी वर्ष 2020 में

स्वामी का बास निवासी रामवतार रंगर से हुई थी। दोनों के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था। रामवतार बेरोजगार था। जिसके चलते आप दिन कमावसुनी होती रहती थी। जहां शुकुवार रात विवाद बढ़ने पर आरोपी ने गुस्से में आकर पत्नी सुनीता का चाकू से गला रेत दिया। हमले के दौरान सुनीता ने बचने का प्रयास किया। जिससे

कमरे में खून फैल गया। हत्या के बाद आरोपी ने खुद के गले पर भी चाकू से वार कर आत्महत्या का प्रयास किया। लेकिन बच गया और रातभर पत्नी के शव के पास ही बैठा रहा। जब शनिवार सुबह करीब 6 बजे परिजनों ने गेट के पास सुनीता का शव और पास में घायल रामवतार को देखा। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और महिला का शव को पोस्टमार्टम के लिए सीएसएस चाकसू की मोचरी मिजबाया। जबकि आरोपी को उपचार के बाद हिरासत में ले लिया गया। मुत्तकार के थार्ड मुकेश ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज उपीडन का आरोप लगाते हुए हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी है।

जयपुर । चाकसू क्षेत्र के स्वामी का बास गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पति ने पत्नी को चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी और पूरी रात शव के पास बैठा रहा। घटना शुकुवार देर रात की बताई जा रही है। थानाधिकारी मनोहर लाल के अनुसार सांगानेर के रथपुर निवासी सुनीता (25) की शादी वर्ष 2020 में

सूने मकानों में चोरी करने वाले दो गिरफ्तार

जयपुर । जयपुर पुलिस की खोराबीसल थाना पुलिस ने सूने मकानों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले दो शांतिर बद्माशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कर्चनी, कालवाड और खोराबीसल थाना क्षेत्रों में एक दर्जन से अधिक वारदातें करना कबूल किया है। जिनके पास से सोने-चांदी के रोडकी करीब और रात में ताला तोड़कर जेवर, नकदी व कीमती सामान चुरा लेते थे। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने कर्चनी क्षेत्र में किराए पर एक मकान लेकर उसे सेफ हाउस बना रखा था। चोरी का माल और नकदी मकान की फॉल्स सीलिंग में छिपाकर रखते थे। जिससे किसी को भनक तक नहीं लगती थी। थानाधिकारी सुरेंद्र चोरी के अनुसार आरोपियों से 3 जोड़ी सोने की बालियां, 4 सोने की पातडियां, 1 सोने की अंठी, 7 चांदी की अंगुठियां, 5 जोड़ी चांदी की पायजमे, चांदी के सिक्के सहित नकदी बरामद की गई है। पुलिस आरोपियों ने अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है।

जयपुर । जयपुर पुलिस की खोराबीसल थाना पुलिस ने सूने मकानों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले दो शांतिर बद्माशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कर्चनी, कालवाड और खोराबीसल थाना क्षेत्रों में एक दर्जन से अधिक वारदातें करना कबूल किया है। जिनके पास से सोने-चांदी के रोडकी करीब और रात में ताला तोड़कर जेवर, नकदी व कीमती सामान चुरा लेते थे। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने कर्चनी क्षेत्र में किराए पर एक मकान लेकर उसे सेफ हाउस बना रखा था। चोरी का माल और नकदी मकान की फॉल्स सीलिंग में छिपाकर रखते थे। जिससे किसी को भनक तक नहीं लगती थी। थानाधिकारी सुरेंद्र चोरी के अनुसार आरोपियों से 3 जोड़ी सोने की बालियां, 4 सोने की पातडियां, 1 सोने की अंठी, 7 चांदी की अंगुठियां, 5 जोड़ी चांदी की पायजमे, चांदी के सिक्के सहित नकदी बरामद की गई है। पुलिस आरोपियों ने अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है।

कांग्रेस को रसातल में पहुंचाने वाले गहलोत को पार्टी ने किया साइड लाइन : घनश्याम तिवाड़ी

"गहलोत अपनी खीझ मिटाने के लिए सोशल मीडिया पर कर रहे हैं मिथ्या ट्विट"

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर । भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इंतजार शास्त्र पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत में शास्त्र तो 64 ही हुए हैं, शास्त्र जैसे पवित्र शब्द के साथ इंतजार जोड़ना नहीं चाहिए। वे चाहे तो इजहार नामा कर सकते हैं। गहलोत हारने के बाद अपनी उपेक्षा से पीड़ित होकर हताशा का इजहार कर सकते हैं। गहलोत जब-जब मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने पार्टी को रसातल में पहुंचाया और सत्ता भाजपा के पास आई। इसके चलते कांग्रेस ने तत्त्व ने उन्हें साइड लाइन कर दिया। कांग्रेस पार्टी को रसातल में पहुंचाने वाले गहलोत साहब को दिल्ली में पायलट और राजस्थान में डोटारास के चलते तबज्जो नहीं दी जा रही, ऐसे में वे सोशल मीडिया पर अपने कार्यों का इजहार कर रहे हैं। तिवाड़ी ने पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के कार्यकाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि "फूलां बाई फूलगी, गेल का दिन भूलगी" लोकोक्ति अशोक गहलोत पर चरितार्थ हो रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत अपना



सांसद घनश्याम तिवाड़ी

कार्यकाल कैसे भूल गए, जब प्रतियोगी परीक्षाओं के मेपरलीक हुए और प्रदेश के युवाओं के साथ कुटाराघात किया गया। गहलोत कैसे भूल गए कि प्रदेश के लिए महत्वकांक्षी परियोजना ईआरसीपी और यमुना जल समझौते को कांग्रेस सरकार ने लटकाने का कार्य किया। गहलोत कैसे भूल गए कि जेजेएम घोटाले में उनकी सरकार के मंत्री से लेकर विभाग के अधिकारी तक जेल पहुंच गए। गहलोत के कार्यकाल में युवा रोजगार के लिए इंतजार कर रहे थे, पेपरलीक रूकने का

इंतजार कर रहे थे, बहन-बेटियां सुरक्षा का इंतजार कर रही थी, किसान जमीन बचाने का इंतजार कर रहे थे और जनता भ्रष्टाचार से मुक्ति का इंतजार कर रही थी। तिवाड़ ने कहा कि सोशल मीडिया पर गहलोत सीरीज चला रहे हैं, जबकि आईपीडी टॉवर प्रोजेक्ट से लेकर टैंडर प्रक्रिया तक अन्यायमितातों से भरा हुआ था। गहलोत सरकार के आंकलन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनके ही कार्यकाल में परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से बढ़कर 700 करोड़ रुपए हो गई, 1500 बेड

वाले टावर के लिए पार्किंग व्यवस्था सिर्फ 190 की गई। यह उनकी जल्दबाजी एवं दिखावे की राजनीति थी। सांगानेरी गेट महिला चिकित्सालय आईपीडी टॉवर को लेकर भी सिर्फ झूठ फैलाया। इसका सिविल खर्च लगभग पूरा हो गया, उपकरणों की वरदी का कार्य प्रगति पर है। गहलोत भूल गए कि उनके कार्यकाल के पहले 2 साल में एक भी पीएचसी नहीं खोली गई, जबकि भजनलाल सरकार ने 6 नई पीएचसी स्थापित की। कांग्रेस ने पहले 2 साल में 53 पीएचसी, भजनलाल सरकार ने 84 पीएचसी खोली, उप जिला अस्पताल गहलोत के कार्यकाल में 1, भजनलाल सरकार ने 61, जिला अस्पताल गहलोत के कार्यकाल में 3 तो भजनलाल सरकार ने 14 और सेटेलैट अस्पताल 2 के मुकाबले 18 खोलने का कार्य किया है। इतना ही नहीं, भजनलाल सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र में दो साल में 50000 से अधिक भर्तियों की, 14 हजार से अधिक प्रक्रियाधीन सरकार के आंकलन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनके ही कार्यकाल में परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से बढ़कर 700 करोड़ रुपए हो गई, 1500 बेड

हकीकत यह है कि 2016 तक राजस्थान में सिर्फ 8 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 23 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए। घनश्याम तिवाड़ ने कहा कि गहलोत ने चुनावी साल में घोषणाओं को बाढ़ ला दी थी, शिलान्यास तो कर दिए, लेकिन उनके लिए बजट में कोई ठोस प्राधान्य तक नहीं किया था। गहलोत ने 5 साल में 4148 घोषणाएं की थी, जिनमें से 2208 पूरी ही नहीं हुईं। करीब 626 घोषणाएं तो ऐसी थीं जिन पर एक रुपए तक खर्च नहीं हुआ। जबकि भजनलाल सरकार ने 2719 बजट घोषणाएं की, जिसमें से 90 फीसदी पर स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं। इनमें से 34 प्रतिशत में कार्य पूर्ण हो गया, 56 प्रतिशत प्रगतिरत हैं और 10 प्रतिशत पर कार्य प्रारंभ होना है। महत्वा गांधी इंस्टीट्यूट्यूट हो या दिव्यांग विश्व विद्यालय, गहलोत ने सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। सिविल लाइन्स आरओबी लेकर गहलोत साहब सफेद झूठ बोल रहे हैं। वर्ष 2021 में शुरू होने वाली योजना में 2022 तक सिर्फ 9 प्रतिशत कार्य हुआ। कांग्रेस के कार्यकाल में सिर्फ 20 प्रतिशत काम ही हुआ था।